Publication Name: The Pioneer
Publication Date: 11/02/2026
Edition: Delhi
Page No: 6
CCM: 180.7

New Dimension of Cooperation

सहकारिता का नया आयाम

पांच फरवरी 2026 को, गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमूल समेत कई सहकारी संस्थाओं के साथ मिलकर सहकारिता मंत्रालय की पहल के तौर पर भारत टैक्सी लॉन्च की। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए भारत टैक्सी उबर और ओला की तर्ज पर टैक्सी सेवाएं प्रदान करेगी। यानी भारत टैक्सी ऐप इस्तेमाल द्वारा अब यात्री अपनी यात्रा बुक कर सकेंगे। भारत टैक्सी की खासियत यह है कि यह किसी कंपनी द्वारा चलाई गई ऐप नहीं है। इस उपक्रम के मालिक स्वयं ड्राइवर होंगे, और अब वे ड्राइवर नहीं सारथी कहलाएंगे। जो यात्रा इस ऐप के माध्यम से बुक की जाएगी उस पर सारथी यानी ड्राइवर को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। गौरतलब है कि उबर, ओला और अन्य टैक्सी ऐप में ड्राइवरों को वर्तमान में 10 से 30 प्रतिशत तक का शुल्क देना पड़ता है। यह आत्मनिर्भर भारत और सहकार से समृद्धि की दिशा में एक मजबूत कदम है। भारत टैक्सी, जो एक कोऑपरेटिव मॉडल पर बनी है, जहां ड्राइवर सिर्फ सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि हितधारक भी हैं। पूर्व के ऐप प्लेटफॉर्म के उलट, भारत टैक्सी का मॉडल जीरो-कमीशन का है, जिससे यह पक्का होता है कि ड्राइवरों को उनकी सही कमाई मिलती रहे। भारत टैक्सी मॉडल के चार स्तंभ हैं सारथियों को ज्यादा आमदनी, सम्मान, सुरक्षा और लाभ में हिस्सा। कैसे बढ़ेगी आमदनी : एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे एक ड्राइवर उबर, ओला या किसी अन्य कंपनी के ऐप पर ट्रिप खोजते हुए काम करता है। इन ऐप्स के कारण कमीशन, आय के नुकसान के कारण नाहक शोषण का शिकार होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई ड्राइवर दिन में 14 ट्रिप करता है और लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिसमें 300 रुपए प्रति ट्रिप का औसत किराया होता है, जिसका मतलब लगभग 14-15 घंटे काम करना हो सकता है, तो उसे 4200 रुपए की आय होगी। लेकिन यह आय वास्तव में उसकी नहीं है, वास्तव में इस आय का आधा भी उसका नहीं है। वास्तव में कंपनी औसतन इस आय का लगभग 25 प्रतिशत प्लेटफॉर्म शुल्क के रूप में लेती है, यानी 1050 रुपए सीधे कंपनी को जाते हैं। फिर, ड्राइवर को टैक्सी चलाने के लिए पेट्रोल/सीएनजी का भुगतान करना पड़ता है, 4 रुपए प्रति किलोमीटर माने तो लगभग 1000 रुपए। या फिर अगर कार किसी बैंक या संस्था से फाइनेंस करवाई गई है तो ईएमआई देनी पड़ सकती है और मेंटेनेंस के लिए भी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। इसलिए, ड्राइवर को एक दिन में 14-15 घंटे काम करने पर सिर्फ 1150 रुपए बचेंगे, औसतन लगभग 80-85 रुपए प्रति घंटा। अब, भारत टैक्सी से जुडने वाले ड्राइवरों के बिना किसी कमीशन मॉडल के, अच्छे-खासी राशि की कमीशन बचाने से, उतने काम से उनकी आमदनी बढक़र 2150 रुपए प्रति दिन हो जाएगी, यानी 160 से 170 रुपए प्रति घंटा। इससे वह ज्यादा आराम के घंटे चुन सकते हैं, जिन्हें वह अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं, जिससे उनका आराम और इनकम दोनों बेहतर होंगे। इसलिए, भारत टैक्सी न सिर्फ ड्राइवर, जो अब सारथी है, की आमदनी बेहतर करती है, बल्कि उसकी और उसके परिवार की खुशी भी बढ़ाती है। सम्मान : सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ड्राइवर को सम्मान के साथ काम मिलेगा। अब वो इस सहकारी टैक्सी सेवा हेतु बनी सहकारी समिति का स्वयं सदस्य भी होगा। यह मोबिलिटी इकोसिस्टम की रीढ़ ड्राइवर को सम्मान वापस दिलाता है, जिसके वो हकदार हैं। सुरक्षा : यही नहीं अब भारत टैक्सी से जुड़े सारथियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, बीमा, सस्ते लोन, सब्सिडी और गिग वर्कर्स के लिए सभी स्कीम जैसे फायदे मिलेंगे। लाभ में हिस्सेदारी : चूंकि भारत टैक्सी मॉडल में ड्राइवर यानी सारथी अब स्वयं भारत टैक्सी सहकारी संस्था के सदस्य होंगे, उन्हें इसके लाभों में भी बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। ये हिस्सेदारी अमूल मॉडल की तर्ज पर होगी। सर्वविदित है कि अमूल मॉडल में दुग्ध उत्पादक किसानों को अमूल सहकारी संस्था में न केवल दूध का सही मूल्य मिलता है, बल्कि उसके लाभ में भी हिस्सेदारी मिलती है। यात्रियों को फायदा : अपना मुनाफा ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, टैक्सी प्लेटफॉर्म आम तौर पर ज्यादा मांग के नाम पर सर्ज प्राइसिंग करते हैं, जिससे यात्रियों को ज्यादा किराया देना पड़ता है, कभी-कभी तो सामान्य किराए से 2 से 3 गुना ज्यादा। भारत टैक्सी के साथ यह तरीका खत्म हो जाएगा।

Publication Name: Amar Ujala
Publication Date: 11/02/2026
Edition: Delhi
Page No: 3
CCM: 87.1

The limit of loan without guarantee can be increased for urban cooperative banks

शहरी सहकारी बैंकों के लिए बढ़ सकती है बिना गारंटी ऋण सीमा

मुंबई। आरबीआई ने मंगलवार को शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया। इसमें शहरी सहकारी बैंकों के लिए बिना गारंटी वाले कर्ज का हिस्सा 10 फीसदी से दोगुना कर 20 फीसदी तक करने की अनुमति का प्रस्ताव है।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण नियमों की समीक्षा के मसौदे के मुताबिक, केंद्रीय बैंक व्यक्तिगत ऋण सीमा बढ़ाने, असुरक्षित कर्ज की परिभाषा को तर्कसंगत बनाने और ऐसे कर्ज के लिए कुल सीमा को संशोधित करने का प्रस्ताव कर रहा है। आरबीआई के दायरे में आने वाले वित्तीय संस्थान, संबंधित पक्ष और आम जनता चार मार्च, 2026 तक मसौदे पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आरबीआई ने कहा, इस सीमा से अधिक अतिरिक्त असुरक्षित ऋण सिर्फ प्राथमिकता क्षेत्र के पात्र कर्जों के संबंध में ही स्वीकृत होंगे, जो प्रति उधारकर्ता 50,000 रुपये की मौद्रिक सीमा पर निर्भर होगा।

इसके अलावा, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए सदस्यों को कर्ज देने की सीमा को भी बढ़ाकर प्रति उधारकर्ता 2.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। टियर-3 और टियर-4 शहरी सहकारी समितियों (यूसीबी) के लिए होम लोन की अवधि और स्थगन जरूरतों को विनियमन से मुक्त करने का प्रस्ताव है। एजेंसी

Publication Name: Haribhoomi
Publication Date: 11/02/2026
Edition: Delhi
Page No: 7
CCM: 120.83

Review to be held in New Delhi under the chairmanship of Shah: Instructions to prepare a presentation on innovation-achievements in cooperation

शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में होगी समीक्षा

सहकारिता में नवाचार-उपलब्धियों का प्रजेंटेशन तैयार करने के निर्देश

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मप्र सहकारिता विभाग में किए गए नवाचार एवं उपलब्धियों से संबंधित प्रजेंटेशन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार की ओर से चाही गई बिन्दुवार जानकारी तैयार की जाए। जानकारी पूर्णतः अद्यतन हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये।

मंत्री सारंग सोमवार को मंत्रालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 17 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाले प्रस्तावित सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में आयोजित की गई थी। मंत्री सारंग ने कहा कि प्रजेंटेशन में सहकारिता विभाग की विशेषताएं एवं उपलब्धियों सहित सीपीपीपी मॉडल, चीता बीज और नवाचारों का भी समावेश किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में किए गए सर्वोत्तम कार्यों की जानकारी भी दी जाए। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र में सर्कुलेरिटी एवं सस्टेनेबिलिटी का भी समावेश किया जाए। सहकारिता में सहकार अभियान के तहत दुग्ध, मत्स्य सहित अन्य सहकारी संस्थाओं तथा उनके सदस्यों के खातों की संख्या दर्शाई जाए। प्रचार-प्रसार की दृष्टि से किए गए प्रयासों को भी बताएं। प्रजेंटेशन को अद्यतन जानकारी के साथ आकर्षक बनाया जाये और कम्पाइल प्रजेंटेशन तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करें।

मंत्री सारंग ने कहा कि पेक्स का बहुउद्देश्यीकरण, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की योजनाएं एवं सहकारिता क्षेत्र को लाभ, वित्तीय सहायता आदि का समावेश किया जाए।

Publication Name: Jagat Kranti
Publication Date: 11/02/2026
Edition: Delhi
Page No: 1
CCM: 63.56

No platform fee, no commission in Bharat Taxi, entire earnings belong to the Sarathi: Amit Shah

भारत टैक्सी में न प्लेटफॉर्म शुल्क, न कमीशन, पूरी कमाई सारथी की : अमित शाह

नई दिल्ली (हि.स.) : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि सारथी की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया सहकारी राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म 'भारत टैक्सी' निजी एग्रीगेटर मॉडलों से बिल्कुल अलग है। इसमें सारथी से कोई प्लेटफॉर्म शुल्क या कमीशन नहीं लिया जाता और यात्रा से होने वाली पूरी कमाई सीधे सारथी को मिलती है। अमित शाह ने मंगलवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारत टैक्सी- सारथी (ड्राइवरों) के हितों को सर्वोपरि रखते हुए तैयार किया गया प्लेटफॉर्म है। यह देश का पहला सहकारी आधारित राइड-हेलिंग ऐप है जो शून्य कमीशन मॉडल पर संचालित हो रहा है।

Publication Name: Jagmarg
Publication Date: 11/02/2026
Edition: Chandigarh
Page No: 8
CCM: 120.17

PACS are joining multi-state cooperative societies: Small farmers will get direct benefit: Suresh Kashyap

बहु-राज्यीय सहकारी समितियों से जुड़ रहे पैक्स छोटे किसानों को मिलेगा सीधा लाभ: सुरेश कश्यप

जगमार्ग न्यूज

शिमला। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने लोकसभा में सहकारिता मंत्रालय से जुड़े तारांकित प्रश्न के उत्तर का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने और छोटे व सीमांत किसानों को सीधे राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में ठोस और संरचनात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्यीय सहकारी समितियों – नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड – के माध्यम से पैक्स को नई पहचान और नए अवसर मिल रहे हैं।

सुरेश कश्यप ने बताया कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देशभर में एनसीईएल से 15,790, बीबीएसएसएल से 34,078 और एनसीओएल से 11,822 सहकारी सदस्य जुड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में भी इन योजनाओं का अच्छा विस्तार हुआ है, जहां 140 पैक्स एनसीईएल, 451 पैक्स बीबीएसएसएल और 139 पैक्स एनसीओएल के सदस्य बने हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र में भी एनसीईएल से 15, बीबीएसएसएल से 12 और एनसीओएल से 4 पैक्स जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि 'भारत बीज' और 'भारत ऑर्गेनिक्स' जैसे राष्ट्रीय ब्रांड किसानों को बेहतर मूल्य, प्रमाणिकता और बड़े बाजार तक पहुंच प्रदान करेंगे। इससे बीज गुणवत्ता सुधार, ऑर्गेनिक उत्पादों के प्रमाणीकरण और कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय द्वारा राज्यों की नोडल एजेंसियों के साथ एमओयू के माध्यम से सदस्यता विस्तार का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पैक्स और किसानों को सीधे जोड़ा जा सके।